(b) if so, the subjects liekly to be discussed at this one day meeting of the Sixth Summit; and

(c) what precaution India has taken to forestall Pakistan again using the Summit forum for raising the Kashmir issue?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) The Prime Minister of India will attend the 6th SAARC Summit rescheduled to take place at Colombo on December 21, 1991.

(b) The Summit is expected, *inter alia*, to discuss programmes for regional cooperation in the fields of Trade. Manufactures and Services, Environment, Terrorism, Shelter, Poverty-alleviation and Women and Children.

(c) The SAARC Charter specifically rules out the raising of bilateral and contentious issues in SAARC fora.

उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े की बिक्री

*354. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्ष में उत्तर प्रदेश में कितने मीटर जनता कपड़ा बेचा गया है ;

(ख) इस कपड़े को किस माध्यम से बेचा गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा जनता कपड़े की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए बिक्री हेतु वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमश: 107.11 मिलियन वर्ग मीटर और 109.53 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़ा वितरित किया गया।

(ख) उत्तर प्रदेश में लक्षित उपभोक्ताओं को निम्नलिखित विपणन अभिकरणों द्वारा जनता कपड़ा वितरित किया जाता है :-

1. उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य और अनिवार्यक वस्तु निगम लि०, कानपुर।
3. भूतपूर्व सैनिक उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, लखनऊ।
4. भेलूपुर उपभोक्ता सहकारी भंडार, वाराणसी।
5. आगरा मंडल विकास निगम, आगरा।
6. कानपुर थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, कानपुर।
7. जिला सहकारी संघ, कानपुर।
8. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कानपुर (एन.सी.सी.एफ.)
9. कानपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति, कानपुर।
10. फतेहपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति, फतेहपुर।
11. केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, भिलाई-पुर।
12. उत्तर प्रदेश पुलिस, कानपुर।
13. इलाहाबाद मंडल विकास निगम, इलाहाबाद।

उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर और उ०प्र० औद्योगिक सहकारी संघ, कानपुर को अपने कुल जनता कपड़े के उत्पादन का सामान्यत: अधिकतम 15% तक उनके अपने खुदरा शोरूम के माध्यम से बिक्री करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ग) केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 1990 से प्रभावी संशोधित मार्गदर्शिका में जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत उत्पादित प्रत्येक कपड़े का न्यूनतम गुणवत्ता स्तर निर्धारित किया है। अच्छी किस्म के कपड़े के उत्पादन में और वृद्धि करने के उद्देश्य से "ग्रे" कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कुल जनता कपड़े के उत्पादन का 25% से अधिक नहीं होगा। केंद्र सरकार के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनता कपड़े की गुणवत्ता स्तर सहित इस योजना के कार्यान्वयन के अन्य कार्यों की देख-रेख करने के लिए सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बुनकर सेवा केंद्र भी कार्यान्वयन अभिकरणों को कपड़े की वर्तमान क्वालिटी में सुधार करने और साथ ही नए प्रकार के कपड़े तैयार करने के लिए सहयोग देते हैं।

कोयले के आयात बिल पर रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

*355 श्री रणजीत सिंह :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आयातित कोयले की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के वर्ष के दौरान कोयले का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश को रुपये के अवमूल्यन के कारण कोयले के आयात पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि का भुगतान करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कोयले का कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है और उस पर कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयला, कोक तथा ब्रिकेट्स आदि के आयात में वर्ष 1988-89 के 48.43 लाख टन से वर्ष 1990-91 में 59.96 लाख टन तक की वृद्धि हुई।

(ग) जी, हां। भारतीय रुपए की विनियम दर में दुर्लभ मुद्रा की तुलना में गिरावट आने के कारण कोयले की प्रति यूनिट आयात लागत चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में भारतीय रुपए में ऊंची रहेगी।

(घ) कोयले की चालू वर्ष के दौरान संभावित आयातित मात्रा और इस आयात के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय की राशि का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है।

Loan from foreign banks for purchase of a Boeing-747 Aircraft

*356. SHRI NARAYANASAMY :
SHRI SURESH KALMADI :

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether Air India has signed any financing loan agreement with the Citibank the Australia Bank and the New Zealand Bank for purchase of a Boeing 747 Aircraft; and

(b) if so, what are the terms of the agreement for such a loan and how the aircraft is proposed to be purchased?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) and (b) Government have approved the financing of the acquisition of four Boeing 747-400 aircraft by Air India through a foreign exchange loan facility from Citi Bank and ANZ Bank consisting of Bridge Loan Facility for US£ 60.416 million and a Term Loan Facility amounting to US£ 494.760 million,